bjpkamaljyoti@gmail.com संवत 2076 युगाब्द 5120 मूल्य : ₹10 अंक – 13, फरवरी प्रथम अंक 2021, कुल पृष्ठ – 32

वर्तमान

कमल ज्योति

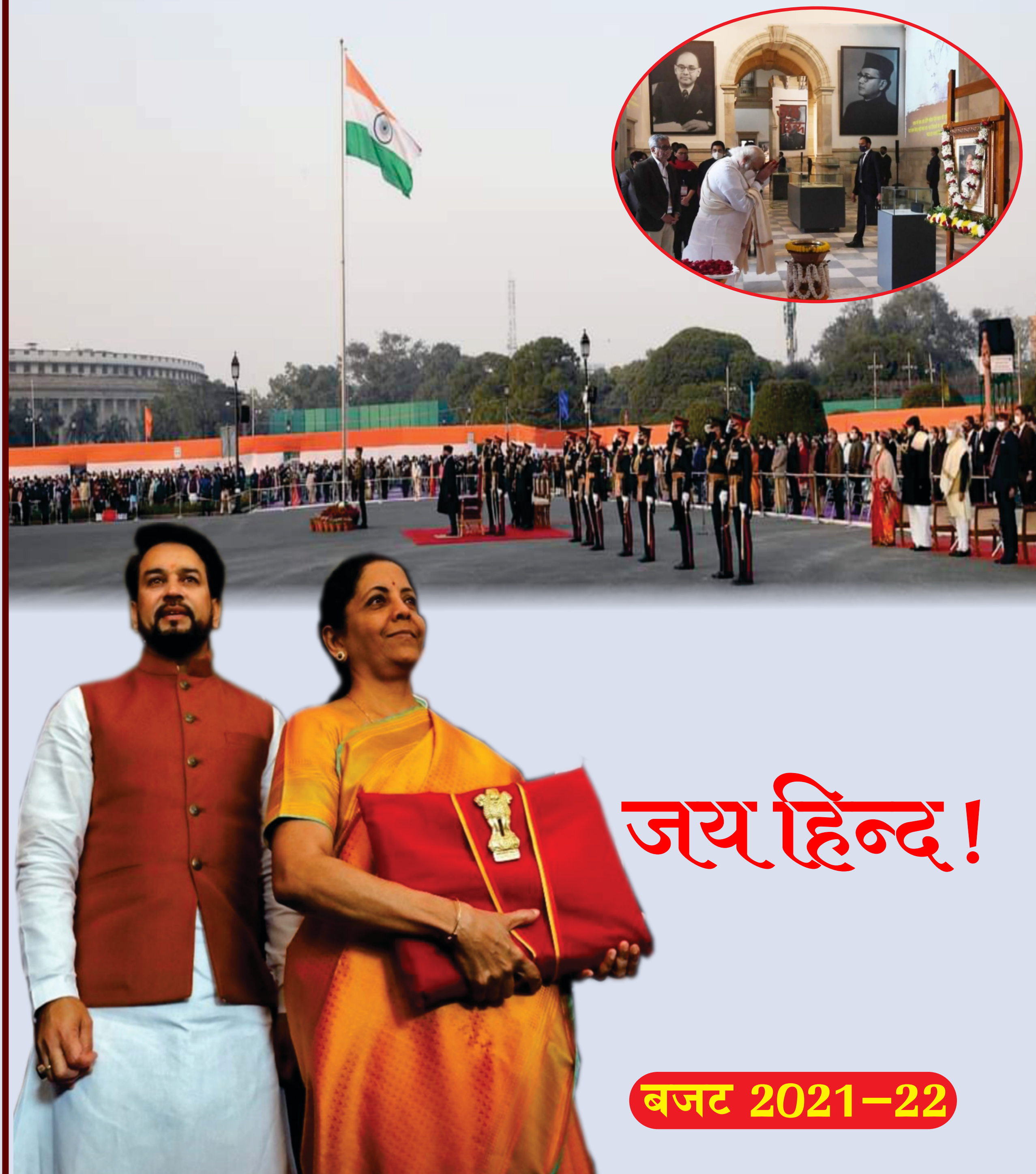

जय हिन्द !

बजट 2021–22

विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण

कानपुर देहात में किसान सम्मेलन

सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण

चौरी-चौरा के शहीदों को श्रद्धांजलि

कार्यालय में नवनिर्मित बैठक भवन का उद्घाटन

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह

सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार

प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय
कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक
नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

संपादकीय

आखिर आ गया अपना स्वप्निल बजट

भारत में अब तक व्याप्त समस्याओं के लिए 1991 के सुधारों को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति रही है। भारत में अब तक के इतिहास में सुधारवादी दृष्टिकोण के पल बहुत कम रहे हैं। इसलिए जब सुधार की बेला आती है तब उसको लोग स्वप्निल कहने लगते हैं। लेकिन कोबिड काल की समाप्ति के बाद जब भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण ने अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया तब उसके गुणकारी रूप में शेयर बाजार से लेकर उद्योग जगत तक छलांग लगाने लगा। वैसे में इस बार का बजट पिछले 30 वर्षों में भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पहला बड़ा बदलाव लेकर आया है। यह बदलाव सही दिशा में भी है। यह वैचारिक स्तर के अलावा समझदारी के स्तर पर भी है। अगर इसे राजनीतिक दृष्टि सें कहा जाए तो यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के समय पेश किया गया पहला अपना बजट है। अब तक पेश किए गए सारे बजट में पुरानी नीतियों में बदलाव दिखता था।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के परवर्ती इंडिया शाइनिंग काल में यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह ने तीन बजट पेश किए थे। तमाम गतिरोधों और सीमा शुल्क एवं कर कटौतियों के बावजूद वह एक बढिया समय था। लेकिन, तब सुप्रीम अदालत के एक फैसले ने निजीकरण की रफ्तार रोक दी थी। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह के समय आर्थिक सुधारों का सिलसिला करीब 18 महीनों में ही रुक गया था। पी. चिदंबरम ने एक साल ही ऐसा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को 2004 में मिली औचक पराजय के बाद बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की नई सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समावेशी विकास के नए समीकरण को अपना लिया। उस समय चुनावी नतीजे का कई लोगों ने मतलब निकाला था कि गरीबों ने आर्थिक प्रगति पर राजग सरकार के जोर को नकारते हुए संप्रग को मत दिया है। पर, किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच सिर्फ सात सीटों का अंतर था और वह भी मामूली मतों से जीती गईं थीं।

लेकिन अंततः संप्रग सरकार का दूसरा कार्यकाल आने तक कांग्रेस की कलई खुल गई। संप्रग सरकार इतना नहीं चली कि, सोनिया गांधी एवं उनकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बढिया मॉनसून और क्रिकेट में जीत की गारंटी देने वाले कानून बना सके।

उस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदाताओं ने दो बार बहुमत देकर एक कॉकस को कुतर्क से वंचित कर दिया था। श्री मोदी ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराते हुए पहला बड़ा कदम उठाया था। नोटबंदी ने देश को नकली नोटों के कारोबार से किनारे किया और अर्थप्रणाली को धीरे–धीरे समावेशी नीतियों की ओर लेकर बढ़ चली।

इस बीच दूसरे कार्य काल में श्री मोदी को महामारी की वजह से उपजे हालात से मदद मिली और इस बजट ने घड़ी को पीछे कर दिया। एक लोकतंत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से लेकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, कल्याण एवं बाजार तक सब कुछ राजनीति से ही तय होता है। एक लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था का प्रबंधन एवं दिशा राजनीति ही तय करती है। लेकिन 2021 के बजट ने बताया है कि आर्थिक नीतियों में राजनीति को किनारे भी किया जा सकता है अगर आपके अंदर भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति हो।

डिजिटल तकनीक के समय पर आप अब तरकीब से सुधार नहीं कर सकते हैं। बगीचे में नीचे लटक रहे सारे फलों को पहले ही तोड़ा जा चुका है। अर्थशास्त्री एवं लोक वित्त विशेषज्ञ ही बजट के बारीक बिंदुओं को समझ पाएंगे। मेरा नजरिया राजनीतिक है। मैं इसे भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक बदलाव के तौर पर देखता हूं। इस बजट में सबसे अच्छी खबर यह है कि कराधान पर कोई खबर नहीं है। सभी कर दरें पुराने स्तर पर ही हैं।

संपादकीय

यह एक प्रगति है और यह राजनीतिक है।

सैकड़ों बुरे खयाल चर्चा में थे। कर दरों में बढ़ोतरी, संपत्ति जब्त करने, असफल हो चुके उत्तराधिकार एवं संपत्ति करों की वापसी, अप्राप्त पूंजी लाभ पर भी कर लगाने जैसे प्रस्तावों का जिक्र हो रहा था। प्रतिष्ठित लोगों में उन विचारों पर अधिक जोर था। अगर बजट में इन खयालों पर अमल किया गया होता तो एक दिन बाद हम बजट को किस रूप में देख रहे होते? इसे अब केवल सोचा ही जा सकता है क्यों कि हर कयास पर अब विराम लग गया है।

सरकार की इस बात के लिए सराहना करनी होगी कि उसने असाधारण रूप से यह साहसी नीतिगत कदम उठाया। हकीकत तो यह है कि वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव भी रखा है। यकीनन इससे नीतिगत अवरोध टूटेंगे और एक नई शुरुआत होगी। इस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए सरकार ने नीति आयोग से कहा है कि वह रणनीतिक विनिवेश वाली कंपनियों की सूची तैयार करे। इस नीति के कई लाभ होंगे। यह मानना अहम है कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों की मौजूदगी प्रायः विसंगति पैदा करती है और निजी क्षेत्र की कंपनियों को बाधित करती है जबकि उन्हें अधिक कठिन वित्तीय हालात का सामना करना होता है। इतना ही नहीं बड़ी तादाद में सरकारी कंपनियां घाटे में हैं और वे सरकारी वित्त पर बोझ के समान हैं।

उदाहरण के लिए भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट दर्शाती है कि मार्च 2018 में समाप्त वित्त वर्ष में 184 सरकारी कंपनियों को कुल मिलाकर 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ और 77 कंपनियों का विशुद्ध मूल्य पूरी तरह नष्ट हो गया। समस्या यह है कि मुनाफे में चल रही सीपीएसई का प्रदर्शन भी अधिकांश मानकों पर निजी क्षेत्र की समकक्ष कंपनियों की तुलना में काफी खराब है। ऐसे में बड़ी तादाद में सीपीएसई की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बेहतर यही होगा कि सरकार या तो उनका निजीकरण कर दे या उन्हें बंद कर दे। चूंकि सरकार की वित्तीय स्थिति भी दबाव में है इसलिए विनिवेश प्राप्तियों का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि अधिकांश सीपीएसई का मुनाफा पेट्रोलियम और कोयला जैसे क्षेत्र से आता है जहां प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत सीमित है। सरकारी उपक्रमों के लिए निजी क्षेत्र से मुकाबला करना मुश्किल होता है। ऐसे में निजीकरण और प्रबंधन में बदलाव से उनकी क्षमता और उत्पादन सुधर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर कमजोर वाणिज्यिक उपक्रमों के संचालन में ऊर्जा और वित्तीय संसाधन लगाने के बजाय सरकार नीतिगत मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में कामयाब रहेगी। यह सबके लिए बेहतर होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार एक बात को लेकर अत्यधिक ईमानदार है कि वह उन अर्थशास्त्रियों की नहीं सुनती है जो अपने सपने बेचना चाहते हैं। इस मामले में अच्छा ही है कि सरकार ने उनकी नहीं सुनी। इसका कारण यह है कि अर्थशास्त्रियों को बजट के बाद जवाबदेह नहीं होना पड़ता है। जवाब नेताओं को देना पड़ता है। आप पसंद करें या नहीं लेकिन मोदी सरकार ने यह अलहदा राजनीतिक फैसला लिया है। जो सबसे अच्छा निर्णय है।

कई दशकों तक भारत वृद्धि बनाम असमानता के द्वंद्व में उलझा रहा है। यह एक बनावटी बहस है। क्योंकि अगर वृद्धि से अधिक असमानता पैदा होती है तो वृद्धि का अभाव क्या करता है? वृद्धि से अमीर और धनवान बनता है लेकिन क्या इससे गरीब और भी गरीब हो जाता है? अमीर तो उस समय भी बढिया स्थिति में होते हैं जब वृद्धि तेजी से कम हो रही होती है। महामारी के साल में करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने के बीच भी कुछ अरबपतियों की संपत्ति बढने पर दुनिया भर में मचे रोने–धोने को ही देख लीजिए।

इस बजट का संकेत यह है कि मोदी सरकार अब अधिक राजस्व के लिए वृद्धि पर दांव लगा रही है। मैं वॉल स्ट्रीट में प्रकाशित माइकल डगलस गॉर्डन गेक्को के लेख में कुछ बदलाव करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा—— बात यह है कि किसी बेहतर शब्द के अभाव में वृद्धि अच्छा है। वृद्धि ठीक है और यह कारगर है। वृद्धि विकासवादी भावना के सार को अपनाती है। जीवन, स्नेह एवं धन अपने तमाम रूपों में वृद्धि करके मानवता को उन्नत करता है।

akatri.t@gmail.com

संगठनात्मक गतिविधियां

ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के साथ बहुत अन्याय किया है : जगत प्रकाश नड्डा

शाहपुर गाँव (पश्चिम बंगाल) में कृषक सुरक्षा सह–भोज

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शाहपुर, मालदा में हजारों किसानों के साथ "कृषोक सुरक्षा साह–भोज" अभियान के तहत दोपहर का भोजन किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अब तक लगभग 35 लाख किसानों ने खुद को कृषि विकास अभियान से जोड़ा है। यह अभियान 35,000 गाँवों तक पहुँच गया है और इसके अंतर्गत लगभग 33,000 ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है। बहुत जल्द हम पश्चिम बंगाल के 40,000 गाँवों में पहुँचेंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि, ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के साथ बहुत अन्याय किया है। ममता दीदी ने अपने अहंकार और जिद्दी स्वभाव के कारण इस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया, जिसके कारण लगभग 70 लाख किसान इस योजना के लाभ से वंचित थे।

उन्होंने कहा कि आज मैं आपको शपथ दिलाता हूं और मैं पश्चिम बंगाल के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी सरकार बनाने के बाद, हम किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें छोड़ा नहीं

जाए। पार्टी अपनी आय बढ़ाने की दिशा में भी काम करेगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया है। किसानों ने जिस तरह से कृषकों के अभियान में रुचि दिखाई है और जिस तरह से उन्होंने इस साह–भोज का आयोजन किया है, उससे उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब तक किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 7 किस्त या लगभग 14,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन ममता दीदी की किसान विरोधी नीतियों के तहत पश्चिम बंगाल के लगभग 70 लाख किसान इस योजना से वंचित हैं। ममता दीदी ने किसानों को धोखा दिया है और उनका भरोसा तोड़ा है।

श्री नड्डा जी ने कहा कि ममता दीदी, अब आपके लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव बंद हो रहे हैं लेकिन ममता दीदी ने अभी तक किसानों की सूची उनके बैंक खातों के साथ केंद्र सरकार को नहीं सौंपी है। उन्होंने कहा कि आज आकाश जय श्री राम के नारों से भर गया है। लेकिन, मैं यह समझने में नाकाम हूं कि ममता दीदी इतनी नाराज क्यों हैं?

अगर ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में किसानों के उत्थान के लिए काम किया होता, तो उन्हें अब कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ता। ममता दीदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी और किसानों को उनका वाजिब हिस्सा मिलेगा।

यदि हम 2016–17 में नाबार्ड द्वारा वर्णित औसत किसान आय का अनुसरण करते हैं, तो उस आंकड़े से पश्चिम बंगाल देश के 29 राज्यों में 24 वें स्थान पर है। यह एक निराशाजनक रिकॉर्ड है।

हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेती के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि किसान अपनी बेहतरी के बारे में सोचने और उस दिशा में काम करने में सक्षम हैं।

पश्चिम बंगाल के लोगों ने पिसी (बुआ) – भाईपो (भतीजे) को अलविदा कहने का मन बना लिया है। उन्होंने चावल लुटेरों और पंडाल चोरों को सबक सिखाने का फैसला किया है। इस राज्य के लोग जानते हैं कि कौन चावल चुरा रहा है और कौन तिरपाल चोर है।

पश्चिम बंगाल में 665 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर लगभग 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अगर हम चावल खरीद की बात करें तो इस खाद्यान्न की खरीद पर लगभग 64,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। सूक्ष्म सिंचाई के लिए नाबार्ड ने 10,000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।

संगठनात्मक गतिविधियां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना निश्चित: अमित शाह

हावड़ा, पश्चिम बंगाल में आयोजित विशाल जन-सभा

ममता दीदी 'माँ, माटी, मानुष' का नारा देते हुए सत्ता में आई थी लेकिन इन 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में माँ, माटी, मानुष का नारा तो न जाने कहाँ गायब हो गया और उसकी जगह तृणमूल कांग्रेस की तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टिकरण के नारे ने ले ली है।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने रविवार 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आयोजित भाजपा की विशाल रैली को वर्चुअली संबोधित किया और विश्वास व्यक्त करते हुए कहा किभाजपा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम एवं पार्टी नेताओं के सहयोग से हम सब मिल कर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनायेंगे और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

हावड़ा में आयोजित रैली में भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले तृणमूल सरकार में मंत्री राजीब बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस से विधायक वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल और पार्थसारथी चट्टोपाध्याय के साथ-साथ हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती एवं अभिनेता रुद्रनिल घोष भी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि शनिवार को रात में ही इन सब ने गृह मंत्री अमित शाह जी से दिल्ली में मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। राजीब बनर्जी के नेतृत्व में सैकड़ों प्रभावशाली व्यक्तित्व ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा में 11 अलग-अलग क्षेत्रों से 25 बड़े संगठनों, जिला पंचायतों एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नेताओं ने भाजपा जॉइन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए सबका हार्दिक स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

हावड़ा में आयोजित रैली में मंच पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय उपस्थित थे तो वहीं दिल्ली में गृह मंत्री जी के साथ प्रदेश के सह-प्रभारी अमित मालवीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा, पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, सुश्री लॉकेट चटर्जी, सुश्री देबोश्री चौधरी, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो एवं सांसद ज्योतिर्मय महतो भी उपस्थित थे।

श्री शाह ने क्षमा मांगते हुए कहा कि जन-सभा में आज मुझे भी आना था लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं आज आप सबके सामने नहीं आ पाया। मैं बहुत जल्द पश्चिम बंगाल आऊंगा और आप सबसे बात करूंगा। राजीब बनर्जी जी मुझसे कल मिले थे। मैंने भारतीय

जनता पार्टी परिवार में शामिल होने के लिए उनका स्वागत किया है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि हम सब मिल कर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनायेंगे और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज इतने सारे लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आये हैं। इससे पहले सुवेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भी कई विधायक, सांसद एवं कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं।तृणमूल कांग्रेस के साथ–साथ कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस से भी अच्छे–अच्छे लोग भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी या फिर वामपंथी पार्टियां, ये जनता की आकांक्षाओं पर बिलकुल भी खड़ी नहीं उतरी।

श्री शाह ने कहा कि 10 वर्ष पहले कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़ कर तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। उस वक्त ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में 'माँ, माटी, मानुष' का नारा देते हुए परिवर्तन की हवा बनाई थी। इस नारे पर विश्वास करते हुए प्रदेश की जनता ने तृणमूल कांग्रेस के हाथों में राज्य की बागडोर सौंपी थी लेकिन आज जब 10 वर्ष पीछे मुड़ कर देखते हैं तो पता चलता है कि इन 10 वर्षों में माँ, माटी, मानुष का नारा तो न जाने कहाँ गायब हो गया और उसकी जगह तृणमूल कांग्रेस की तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टिकरण के नारे ने ले ली है।पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तो दूर की बात, तृणमूल कांग्रेस ने तो प्रदेश को वामपंथी शासन से भी ज्यादा नीचे ले जाने का काम किया है, इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता ममता दीदी को कभी भी माफ नहीं करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता चाहती थी कि प्रदेश के हर घर में बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, शौचालय पहुंचे लेकिन इस दिशा में ममता दीदी ने कुछ भी नहीं किया। जब पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया तो 6 वर्षों में ही देश के हर गरीब के घर में गैस पहुंची, शौचालय पहुंचा, बिजली पहुँची, शुद्ध पीने का पानी पहुंचा और बेघर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना छत भी मिला। उन्होंने कहा किमाननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को सालाना पांच लाख रुपये तक के मुफ्त स्वास्थ्य खर्च का बीमा दिया तो ममता दीदी ने इस योजना को पश्चिम बंगाल में गरीब जनता तक पहुँचने ही नहीं दिया क्योंकि यह माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी।मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर पश्चिम बंगाल के गरीबों ने क्या बिगाड़ा है आपका जो इस योजना का फायदा राज्य के गरीबों को नहीं मिल रहा है? कोई बात नहीं ममता दीदी,

अब ज्यादा समय बचा नहीं है आपके जाने में।राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिससे कि पूरे पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का पूरा पूरा फायदा मिले। इसे आप रोक नहीं सकती ममता दीदी क्योंकि प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल चुकी है जो रुकने नहीं वाली।

श्री शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी, तोलाबाजी का बोलबाला हो गया है, कानून–व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई और राज्य में उद्योग–धंधे चौपट हो गए हैं।पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिवर्तन की लहर चल रही है। जिस तरह से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के अच्छे–अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं ममता दीदी, चुनाव आते–आते आप पीछे मुड़ कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जायेंगी, कोई भी साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा।

ममता बनर्जी सरकार पर पुरजोर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ अन्याय किया है।देश के हर किसानों के एकाउंट में हर साल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये भेज रहे हैं ताकि उन्हें कृषि में सहायता हो लेकिन ममता दीदी ने आज तक पश्चिम बंगाल के किसानों तक इस फायदे को पहुँचने नहीं दिया। जब हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह मुद्दा जोर–शोर से उठाया और पश्चिम बंगाल के किसानों ने इस पर ममता दीदी का विरोध करना शुरू किया तब घबरा कर ममता दीदी ने एक कागज लिखा है कि हम सहमत हैं, आप किसान सम्मान निधि हमें दे दीजिये। ममता दीदी, किसे बेवकूफ बना रही हैं आप? आपके पत्र के साथ किसानों की सूची भी चाहिए, किसानों के बैंक अकाउंट भी चाहिए जिसमें मोदी जी किसानों के पैसे भेज सकें। ममता दीदी, आप सोचती हो कि बंगाल की जनता यह नहीं समझेगी तो यह आपकी भूल है। भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में किसानों के घर–घर जाएंगे और यह बात उन्हें समझाएंगे कि ममता बनर्जी आपको प्रधानमंत्री जी द्वारा भेजे जा रहे 6,000 नहीं पहुंचने दे रही।

श्री नड्डा ने कहा किस्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुवर रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान विभूतियों की पावन भूमि पश्चिम बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने रक्तरंजित कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की भूमि को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार ही रोक सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां–जहाँ एनडीए की सरकार चल रही है, हर जगह जन–कल्याण के कार्य चल रहे हैं और विकास की धारा बह रही है लेकिन पश्चिम बंगाल में भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे कोई एजेंडा ही नहीं है।

माननीय गृह मंत्री ने कहा किप्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार जन–कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है जबकि ममता दीदी सरकार भतीजा–कल्याण में व्यस्त है। तृणमूल सरकार के लिए बंगाल की जनता का कल्याण एजेंडा ही नहीं है।उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना निश्चित है। हम पश्चिम बंगाल में एक ऐसी विकासोन्मुखी सरकार देंगे जो न केवल प्रदेश की कानून–व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाएगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन करेगी, महिलाओं को भी सुरक्षित करेगी, घुसपैठ को भी पूर्ण रूप से खत्म करेगी, आयुष्मान भारत एवं प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना को लागू करेगी और राज्य के हर सरकारी कर्मचारी को उनके अधिकार का वेतन देगी। राज्य में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार तोलाबाजी और तुष्टिकरण को पूरी तरह से समाप्त करेगी।मुझे विश्वास है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पश्चिम बंगाल में हमारे 'सोनार बांग्लाश अभियान को बल मिलेगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं गुरुवर रवींद्रनाथ टैगोर जी के सपनों का बंगाल बनाने में हम सफल होंगे।

बजट 2021 : अहम बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को लोकसभा में देश का आम बजट प्रस्तुत किया। ऐसे समय में जबकि देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है तो बजट से काफी उम्मीदें थीं जिस पर केन्द्र सरकार पूर्ण रूपेण खरी उतरी है।

कोविड–19 महामारी से दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है और भारत के संदर्भ में भी यह बात शत–प्रतिशत लागू होती है। कोविड–19 महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जीडीपी घटा है, बेरोजगारी बढ़ी है और बैंकिंग सेक्टर भी गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। हालांकि, बैकिंग सेक्टर तो पहले से ही संकट के दौर में है। बैंकों ने बढ़ेते एनपीए ने आर्थिक तस्वीर को बदल कर रख दिया है। इसके बाद भी यह एक सकारात्मक बजट है जिसमें गांव–गरीब–किसान को बदलने की स्पष्ट सोच दृष्टिगत हो रही है।

बजट का लक्ष्य विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश पर है। इसीलिए 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है।

पहला स्तंभ –	स्वास्थ्य और कल्याण
दूसरा स्तंभ –	भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना
तीसरा स्तंभ –	आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
	मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
पांचवा स्तंभ –	नवाचार और अनुसंधान और विकास
छड़ा स्तंभ –	न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

आगे के पृष्ठों पर देखें बजट विशेष

बजट 2021

इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकास पर जोर

❖ ढांचागत विकास के लिए सराहनीय कदम

❖ सरकार ने आधारभूत संरचनाओं के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया है

भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ तिमाही पहले तक आइएमएएफ और अन्य संस्थाओं के हिसाब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यस्थाओं में शामिल थी। परंतु बीते कुछ तिमाहियों में जीडीपी के विकास की गति पिछले कई दशकों मे सबसे कम रही है। अर्थव्यवस्था में आये इस नाटकीय बदलाव ने सभी को चकित किया है।

हालांकि आइएमएफ ने इसे शार्ट–टर्म समस्या बताया है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान समस्या का कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आयी मांग में कमी है, इस कमी से निपटने में आधारभूत संरचनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) में निवेश एक प्रभावकारी तरीका हो सकता था। सरकार अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए यह कर दिया है।

यातायात संबंधी

यातायात संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के समुचित विकास के लिए सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 1,77,000 करोड़ रुपये के निवेश की बात कही है। इस हेतु सरकार तकरीबन 9,000 किलोमीटर के नये इको डेवलपमेंट कॉरिडोर बनायेगी, जिसमें तकरीबन 2500 एक्सेस कंट्रोल हाइवे होंगे। इस निवेश से पूरे देश में न सिर्फ यातायात सुविधाओं का विकास होगा, बल्कि रोजगार भी पैदा होगा।

तटीय क्षेत्रों का विकास

तटीय क्षेत्रों के विकास हेतु इस वित्तीय वर्ष में सरकार कुल 200 तटीय और पोर्ट हाई–वे में निवेश करेगी। इनके विकास से इन क्षेत्रों में भी यातायात एवं सामान की ढुलाई सुगम होगी और रोजगार सृजित होगां। इसी तरह सीमावर्ती क्षेत्रों में यातायात के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबा स्ट्रैटिजिक हाइ–वे बनायेगी। इससे रोजगार की नयी संभावनाएं सृजित होंगी, साथ ही इन क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनेगी। इन परियोजनाओं के अलावा सरकार आगामी वर्षों में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस–वे सहित दो अन्य कॉरिडोर को 2023 तक पूरा करेगी।

उड़ान योजना

उड्डयन क्षेत्र में उड़ान योजना के अंतर्गत 100 एयरपोर्ट विकसित किये जायेंगे तथा विमानों की संख्या को दोगुना की जायेगी। सरकार चार रेलवे स्टेशनों का पुर्नविकास करेगी एवं रेलवे की सौर उर्जा के प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ायेगी। ये सारी परियोजनाएं देश में न सिर्फ यातायात को सुगम बनायेंगी, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार की संभावनाओं को भी पैदा करेगी।

नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी

सामान के ढुलाई हेतु सरकार अपनी महत्वाकांक्षी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा करेगी, जो पूरे देश में सामानों के ढुलाई को सुगम करने एवं माल की इन–ट्रांजिट बर्बादी को कम करने में मदद देगी। यदि ये पॉलिसी ी तरीके से लागू हुई, तो कृषि उत्पादों की ढुलाई के दौरान होनेवाली बर्बादी में कमी आयेगी, जो अंततः किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी।

पाइप द्वारा पेयजल

भारतीय घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 3,60,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस निवेश के बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। साथ ही सरकार कृषि क्षेत्र एवं सिंचाई के विकास के लिए 2,83,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनायी है।

कृषि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की समस्या को देखते हुए सरकार ने स्वयंसेवी निकायों के द्वारा कोल्ड स्टोर का विकास किया जायेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज

सरकार ने 1,23,000 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के लिए आवंटित किया है और 12,300 करोड़ का निवेश स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करेगी। यदि ये सभी योजनाएं समय से कार्यान्वित हो जाती हैं, तो लाखों हाथों को रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण मजदूरों एवं किसानों की आय में महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है, जो अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने में सहयोगी होगा।

बजट 2021 : विश्लेषण

रेवड़ियां बांटने का समय समाप्तं अब अर्थव्यवस्था की मजबूती

कोबिड 2019 को लेकर लोगों को बजट में लुभावनी घोषणाओं की उम्मीदें थीं। लेकिन एक सख्त नजर आने वाला सर्वसमावेशी बजट पेश कर सरकार ने साफ कर दिया कि यह रेवड़ियां बांटने का वक्त नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास को गति देना जरूरी है। इसलिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यह अच्छा बजट साबित हो रहा है। देश के शेयर बाजार की छलांग इसी ओर संकेत कर चुकी है जो 51,000 जा चुका है।

बजट से पूर्व किसानों को सरकार ने किसान सम्मानि निधि का तोहफा दिया था। इसलिए केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार से लुभावने बजट की आस छूटी नहीं थी। लेकिन चुनाव पूर्व कई अहम योजनाओं की घोषणाएं कर चुकी सरकार के समक्ष राजस्व बढ़ाने की चुनौती थी। जिसका प्रभाव बजट में है।

पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम ऐसे ऐलान हैं जिसके जरिए अगले 10 साल में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जाने हैं। ये ऐसे कदम होंगे कि हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2025 के आस पास हासिल कर सकते हैं। इस बजट में किसान, गरीब और मध्यमवर्ग सभी का ध्यान रखा गया है। सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग के ऊपर कोई टैक्स का बोझ नहीं लादा है बल्कि घर और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को अतिरिक्त राहत ही दी है। जीरो बजट फार्मिंग के जरिए किसानों की उपज बढ़ेगी जो सभी के लिए राहत होगी।

रोजगार का मुद्दा चुनाव के दौरान भी अहम था और आज भी देश की नजरें इसी तरफ लगी हैं। रोजगार तभी बढ़ेंगा जब अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था में तेजी होगी तो कर राजस्व भी बढ़ेगा। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तत्काल राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थो पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई अहम

बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर सौ फीसदी करने का फैसला भी अहम है। देश में छह फीसदी लोगों के पास आज बीमा है और इसमें विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। सौ फीसदी निवेश को मंजूरी से विदेशी बीमा कंपनियां देश में कारोबार कर सकेंगी और इससे बड़े पैमाने पर नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। व्यक्तिगत करों की दरों में सरकार ने जो राहत लोगों को देनी थी वह अंतरिम बजट में दे दी है। इसलिए इसे छेड़ा नहीं गया। जबकि किफायती फ्लैटों की खरीद में डेढ़ लाख तक की ब्याज पर अतिरिक्त छूट कुछ लोगों को फौरी राहत दे सकती है। यह निर्णय भी रियल स्टेट सेक्टर को गति देने के लिए लिया गया है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी और सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री के फैसले भी अहम हैं। दरअसल, जीएसटी लागू होने के बाद भी राजस्व में जितनी बढ़ोत्तरी की उम्मीद की जा रही थी वह नहीं हुई। आज 28 लाख करोड़ के सालाना बजट के लिए करों की आय महज 20 लाख करोड़ ही है। ऐसे में सरकारी क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और सरकारी उपक्रमों के विनिवेश से पैंसा जुटाना जरूरी हो जाता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए सरकार की क्या रणनीति होगी, कहां से आएगा पैसा। इस दिशा में सरकार निजी क्षेत्र के जरिए आने वाले निवेश को बढ़ावा देने के कदम उठा रही है। देश के ऊपर विदेशी कर्ज काफी कम है। ऐसे में भारत विदेशों से बॉन्ड के जरिए ज्यादा रकम जुटाकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम करके आर्थिक दिशा में तेजी लाएगी। सरकार ने इस मोर्चे पर अलग फंड का प्रावधान तो किया ही है। निजी क्षेत्र की तरफ से भी बड़े निवेश की उम्मीद है।

निवेश की संभावनाएं अपार

सरकार ने बजट में 25 फीसदी कॉरपोरेट के दायरे में 400 करोड़ तक की कंपनियों को शामिल कर लिया है। वहीं कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा भी बजट में बढ़ाई गई है। इसके अलावा टैक्स स्क्रूटनी में भी सरलता लाई जा रही है। ऐसे में देश में निजी क्षेत्र की तरफ से नए निवेश की संभावनाएं अपार हैं।

देश में सबको घर

सरकार ने पूरे बजट को ही आम लोगों से जोड़कर रखा है। देश में सबको घर मिले इस दिशा में सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। बजट में भी इस दिशा में टैक्स छूट दी गई है। इस टैक्स छूट के जरिए उसे न सिर्फ अपना घर खरीदना आसान होगा बल्कि उसकी वास्तविक आमदनी में भी इजाफा होगा। फिर बाकी योजनाओं के जरिए होने वाले सकारात्मक बदलाव का फायदा भी आम लोगों को ही मिलेगा। इसके अलावा देश मे सरकारी कंपनियों के पास खाली पड़ी जमीन पर सस्ते घर बनाने की रणनीति तैयार है जल्द ही उस पर काम शुरू किया जाएगा।

निवेश के जरिए रोजगार

देश में विदेशी निवेश बढ़ने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में होने वाले बड़े निवेश के जरिए नौकरियों की अपार संभावनाएं आने वाली है। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त आयकर छूट का ऐलान किया है। इससे देश में नई क्रांति होगी। ये सेक्टर पूरी तरह से देश में पनपेगा और बड़ा होगा। यही नहीं इसके लिए बड़े पैमाने पर बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा।

आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद

अरुण कान्त त्रिपाठी

बजट में कोरोना काल में देश के स्वास्थ्य और आर्थिक सेहत को हुए नुकसान की भरपाई और आगे बढ़ने के रोडमैप को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, और अधिकतर प्रावधान इसी लक्ष्य की पूर्ति के प्रारंभिक प्रयास हैं। चाहे बजट का आकार हो या प्रावधानों के प्रकार, दोनों का फोकस इसी बात पर है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार कैसे दी जाए?

आकार के लिहाज से देखें, तो कोरोना की असाधारण परिस्थितियों के बीच भी 34.83 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करना कोई साधारण काम नहीं है। वैसे तो यह आंकड़ा ही अपने–आप में काफी बड़ा है, लेकिन यह भी पूरा नहीं है। कोरोना काल में आम आदमी से लेकर अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के तीन अलग–अलग बूस्टर डोज भी जारी किए थे। इन सबको जमा किया जाए, तो यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मुश्किल वक्त में अपना खजाना खोलने में सरकार ने कोई कंजूसी नहीं की है।

साल 2021–22 का बजट पेश है और अब इसे अलग–अलग कसौटी पर कसा जा रहा है। सियासी जमात इसमें अपनी गुंजाइश और बाजार अपना भविष्य तलाश रही है। चूंकि यह बजट बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों के बीच पेश हुआ है, इसलिए इसका फोकस और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, और इसमें भ्रम की कोई स्थिति नहीं दिखती।

आमूल–चूल बदलाव

बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो हेल्थ सेक्टर को ही मिली है। पिछले आवंटन के लिहाज से देखें, तो यह तवज्जो उम्मीदों से भी परे है। इस बार स्वास्थ्य के लिए दो लाख 23 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 137 फीसद ज्यादा है। इसमें कोरोना से तात्कालिक लड़ाई के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान तो किया ही गया है, लेकिन जो कदम ज्यादा दूरगामी दिखता है, वो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरु आत जिसके लिए 64,180 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। योजना के तहत 70 हजार गांवों में वेलनेस सेंटर, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, नौ बायो सेफ्टी लेवल लैब, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को कनेक्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू करने के साथ ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को मजबूत बनाया जाएगा। इसके पीछे सोच कोरोना से मिले सबक और किसी अगली महामारी के लिए पहले से मुकम्मल तैयारी की दिखती है। गांव से लेकर शहर तक स्वास्थ्य ढांचे में आमूल–चूल बदलाव की यह योजना अगर साकार हो जाती है, तो यह बीमारियों की रोकथाम, चिकित्सा और आम जन के स्वस्थ जीवन के लिहाज से गेमचेंजर साबित हो सकती है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दूरदर्शिता

न्यू इंडिया के नजरिए से इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दूरदर्शिता की नई लकीर खींचने की कोशिश दिखती है। आज दुनिया मैन्युफैक्चरिंग में चीन का विकल्प तलाश रही है और बजट में हुए प्रावधानों से भरोसा मिलता है कि सरकार इस अवसर को भुनाने की रणनीति पर काफी आगे बढ़ चुकी है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात बिल को कम करने के लिए सरकार ने पिछले साल 13 बड़े सेगमेंट को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की थी। बजट में इस बार पीएलआई में नई तकनीक लाने और

अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रु पये खर्च करने का इरादा जताया गया है। बड़े पैमाने पर रोजगार की गारंटी देने वाले टेक्सटाइल सेक्टर को भी अगले तीन साल में निवेश के सात बड़े केंद्र देने की योजना है।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा

बजट के प्रावधानों से ये संकेत मिलते हैं कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत लॉजिस्टिक की लागत को कम रखने और घरेलू माल को वैंकि स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेशनल रेल प्लान और भारतमाला प्रोजेक्ट इसी रणनीति का हिस्सा दिखते हैं। नेशनल रेल प्लान के तहत साल 2030 तक की जरूरतों को देखते हुए कई फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जबकि भारतमाला प्रोजेक्ट में मार्च, 2022 तक ग्यारह हजार किलोमीटर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। देश में सड़कों और रेल लाइनों का जाल बिछ जाने से घरेलू उत्पाद बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक जल्दी पहुंचेंगे और हम कम समय में उन्हें दूसरे देशों में भेज सकेंगे। वहीं, दूसरी रणनीति निवेश बढ़ाने के नये उपाय की तलाश से जुड़ी है। डवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी विकास वित्तीय संस्थान के लिए अलग से विधेयक और 20 हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की घोषणा इसी तलाश का एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि अगले तीन साल में इसका लोन पोर्टफोलियो पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

वोकल फॉर लोकल

एमएसएमई के बजट को दोगुना करने के पीछे भी यही महत्त्वाकांक्षा दिखती है। कृषि के बाद एमएसएमई रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, और कोरोना की सबसे ज्यादा मार भी इसी सेक्टर पर पड़ी है। सरकार इस सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल योजना का मॉडल बनाना चाहती है और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग और पेडअप कैपिटल की सीमा बढ़ाना इस सेक्टर को नई ताकत देने की मंशा दिखाता है।

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट में शहरों में गुणवत्तापूर्ण जीवन की जरूरत को भी पर्याप्त तरजीह दी है। गांवों से शहरों की ओर बेलगाम पलायन को देखें, तो सरकार की इस पहल का दूरगामी महत्त्व समझ में आता है। बजट में स्वच्छ पेयजल, सफाई, प्लास्टिक उपयोग में कमी, पर्यावरण सुधार, कनेक्टिविटी में सुधार जैसी मदों के लिए भी अच्छा–खासा खर्च रखा गया है।

पूरे बजट में दो ऐसे मसले हैं, जिन पर थोड़ी–बहुत गुंजाइश दिखती है। पहला, कृषि जिसके बारे में अनुमान था कि किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार अपना खजाना खोलेगी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार केवल दो फीसद का ही इजाफा हो पाया। हालांकि यह भी सही है कि इस बार एमएसपी के लिए कमिटमेंट और मंडियों को मजबूत बनाने के साथ–साथ जोर गांव–देहात के बुनियादी ढांचे को सुधारने पर भी है, जो आने वाले समय में फायदेमंद होगा।

दूसरा मसला सरकारी संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर है। माना जा रहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की सोच के खिलाफ है, लेकिन सरकार की दलील है कि बेकार संपत्तियां उल्टे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान नहीं करतीं और इनका विनिवेश ही सरकार का राजस्व बढ़ाने के साथ–साथ इन्हें घाटे से उबार सकता है।

अर्थव्यवस्था को रफ्तार

बहरहाल, पूरे बजट को समग्रता से देखने पर पता चलता है कि, सरकार पूंजीगत व्यय के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस बार बजट के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी को 6.6 फीसद बढ़ाकर 4.4 लाख करोड़ रु पए तो किया ही गया है, अगले साल के लिए भी इसमें 25 फीसद तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचेगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे समय पर उठाए गए कुछ कदम और नीतिगत निर्णयों से हमारी अर्थव्यवस्था की रिकवरी दूसरे कई देशों से बेहतर रही है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, औद्योगिक उत्पादन, जीएसटी संग्रह जैसे प्रमुख संकेतक फिर से अपने पुराने स्तर पर आ गए हैं, या उससे आगे भी निकल गए हैं, इन्हीं सब को आधार मानकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5 फीसद तक की ग्रोथ और इसके ग्लोबल इकोनॉमी का विकास इंजन बनने को लेकर आशान्वित दिख रहा है।

इस बजट के दिल में गांव हैं, हमारे किसान हैं : नरेन्द्र मोदी

कोविड के बावजूद आम आदमी पर नया बोझ नहीं डाला गया– बोले प्रधानमंत्री

- ❖ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोविड–19 के दुष्प्रभावों के बीच बजट की सराहना
- ❖ वित्त मंत्री और उनकी टीम ने अगले वित्त वर्ष के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा
- ❖ प्रधानमंत्री बोले देश का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को कोविड–19 महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों के लिहाज से काफी सधा हुआ और बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम आदमी पर नया बोझ नहीं डाला गया जैसा कि आशंका जताई जा रही थी। पीएम ने इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इसके लिए बधाई दी और कहा कि यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए ठोस कदम रखने में मददगार साबित होगा।

बजट का साइज बढ़ाने पर रहा ध्यान

प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे थे कि सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट का साइज बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है, इसमें यथार्थ का अहसास और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिला कर रख दिया। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है।

पीएम ने बताया– बजट में क्या–क्या

प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने बजट के विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए कहा, बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर वर्ग का समावेश भी है। हम इसमें जिन सिद्धांतों को लेकर चले

हैं वो हैं– ग्रोथ के लिए नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए क्षेत्र विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना है।

बजट को बाजार का समर्थन

प्रधानमंत्री ने शेयर बाजार में आए जबर्दस्त उछाल के हवाले से कहा कि इस बजट को भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने कहा, ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं जिसमें शुरू के एक–दो घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। उन्होंने आगे कहा, इस बजट में डेड और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य,पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह–लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

श्री मोदी ने कहा, देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। किसानों को आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव हैं, हमारे किसान हैं।

बजट एक नजर

बजट को सरल शब्दों में ऐसे समझें

50 हजार पर बने रहने के लिए बजट व आय अहम

बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स ने 50,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को छू लिया और पिछले साल मार्च के निचले स्तर से इसमें 90 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। महज 32 कारोबारी सत्र में इसने करीब 5,000 अंक जोड़े हैं। इस तेजी में वैश्विक नकदी, मजबूत एफपीआई निवेश, आर्थिक गतिविधियों में उम्मीद से तेज सुधार और अच्छे बजट की संभावना का योगदान रहा है। कमल ज्योति ने पांच प्रमुख कारक पर नजर डाली जिसके बाद बजअ को सराल रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं।

वर्ष 2021–2022 का 6 प्रमुख बिन्दुओं पर आधारित है:

1. स्वास्थ्य और कल्याण
2. वास्तविक और वित्तीरय पूंजी, और बुनियादी ढांचा
3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार
5. नवोन्मेंष और अनुसंधान और विकास
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

1. स्वास्थ्य और कल्याण

- टीका
- पोषण
- जल आपूर्ति और स्वच्छ भारत मिशन का सर्वव्या पी कवरेज

2. भौतिक या वास्त्विक और वित्तीरय पूंजी एवं अवसंरचना

- आत्मभनिर्भर भारत–उत्पावदन से जुड़ी प्रोत्सांहन योजना
- वस्त्र
- अवसंरचना
- अवसंरचना का वित्त पोषण विकास वित्त संस्थान **(डीएफआई)**
- परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण
- सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना
- रेलवे अवसंरचना
- शहरी अवसंरचना
- विद्युत अवसंरचना
- बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
- वित्तीय पूंजी
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई में बढ़ोतरी
- विनिवेश और रणनीतिक बिक्री

3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

- कृषि
- मछली पालन
- प्रवासी श्रमिक और मजदूर
- वित्तीय समावेशन

4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण
- कौशल

5. नवोन्मेरष और अनुसंधान और विकास

जुलाई 2019 के उनके बजट भाषण में, उन्होंने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की घोषणा की और कहा कि **NRF** का 5 साल का परिव्यय 50,000 करोड़ होगा। जो सुनिश्चित करेगा कि देश के समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय–प्राथमिकता वाले जोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मजबूत बनाया जाए।

6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

न्याय को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए पिछले कुछ वर्षों में ट्रिबुनलों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाने का प्रस्तालव किया।

सरकार ने 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ संसद में राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक पेश किया है। इस बड़े और महत्वसपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2021–2022 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

- गोवा सरकार को पुर्तगाली से राज्य की मुक्ति की जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपये का अनुदान
- एक विशेष योजना के माध्यम से असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा
- पंद्रहवां वित्त आयोग
- 2021–26 को कवर करने वाली अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई थी, जिसमें राज्यों के ऊर्ध्वाधर शेयरों को 41ः पर बनाए रखा गया था
- 15वें वित्तं आयोग ने 2021–2026 की अवधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रधपति को सौंप कर दी है।
- केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ को निधि प्रदान की जाएगी
- सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्व मुखी हिस्साग 41 प्रतिशत पर बरकरार रखते हुए व्याख्यत्मि की टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी है।

- आयोग की सिफारिश पर बजट में 2021–22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 2020–21 में 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रु दिए गए थे।

Part-B

1. प्रत्यक्ष कर

उपलब्धियां

- कॉर्पोरेट टैक्स दर में कमी कर इसे दुनिया में सबसे कम किया
- छोटे करदाताओं के लिए छूट को बढ़ाकर टैक्स बोझ को कम कर दिया गया
- रिटर्न फाइल 2014 के 3.3 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हो गया
- फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की शुरुआत की गई

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

- 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर रिटर्न दाखिल करने से छूट और केवल पेंशन और ब्याज आयय बैंक द्वारा कर काटा जाना
- विवादों को कम करना, निपटान को आसान बनाना
- आय को छिपाने के साक्ष्य के साथ गंभीर कर चोरी के मामले को फिर से खोलने की समय सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल की गई
- एक वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक के लिए यह अवधि प्रधान मुख्य आयुक्त की मंजूरी के साथ 10 वर्षों तक की होगी
- 50 लाख रु तक और 10 लाख आय रु तक के करदाताओं की कर योग्य आय के लिए विवाद समाधान समिति नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी
- 1 लाख से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रु के कर विवादों को निपटाने के लिए 30 जनवरी 2021 तक विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना

NRIs को छूट

- **NRI** द्वारा अपने विदेशी सेवानिवृत्ति खातों के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिसूचित नियम

बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था

95 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन करने वाली संस्थाओं के लिए टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ रु. से बढ़ाकर 10 करोड़ रु किया गया

लाभांश में राहत

- **REIT / InvIT** को लाभांश का भुगतान टीडीएस में छूट
- लाभांश की घोषणा भुगतान के बाद ही लाभांश आय पर अग्रिम कर देयता
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए कम संधि दर पर लाभांश आय पर कर की कटौती
- इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करना
- विनिर्माण के लिए कोष इकट्ठा करने में जीरो कूपन बॉन्डर शुरू किया जाएगा।
- विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बजट में निजी निधि के व्यफय से जुड़ी स्थितियों, वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रतिबंधों और विनिर्माण में सीधे निवेश से जुड़े नियमों को सरल बनाकर राहत प्रदान की गई है।

सभी के लिए घर के लिए सहायता

- सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा।
- उन्होंने सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय–सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है।
- सस्तें किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है।

GIFT सिटी में IFSC को टैक्स इंसेंटिव

- विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों की आय से पूंजीगत लाभ के लिए कर छूट
- विदेशी पट्टों के लिए भुगतान किए गए विमान पट्टे के किराये के लिए कर छूट
- **IFSC** में विदेशी फंड को स्थानांतरित करने के लिए कर प्रोत्साहन
- **IFSC** में स्थित विदेशी बैंकों के निवेश प्रभाग को कर में छूट

टैक्स भरने में आसानी

- सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, लाभांश आय, बैंकों से ब्याज, आदि का विवरण रिटर्न में पहले से भरा होना.
- छोटे ट्रस्टों को राहत

स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए वार्षिक रसीद की छूट सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है

श्रम कल्याण

- नियोक्ता द्वारा कटौती के रूप में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के योगदान की देर से जमा की अनुमति नहीं होगी
- स्टार्ट–अप के लिए कर में छूट के दावे की पात्रता एक और वर्ष बढ़ाई गई
- 31 मार्च, 2022 तक स्टार्ट–अप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट

2. अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- **GST:** अभी तक किए गए उपाय

- **SMS** के जरिए निल रिटर्न
- छोटे करदाताओं के लिए एक तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान
- इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली
- वैलिडेट इनपुट टैक्स स्टेटमेंट
- पहले से भरे हुए एडिट किए जाने वाले जीएसटी रिटर्न
- रिटर्न फाइलिंग के लिए चक्कर काटने से बचना
- जीएसटीएन प्रणाली की क्षमता में वृद्धि
- कर चोरों की पहचान करने के लिए गहन विश्लेषण और एआई का उपयोग

सीमा–शुल्क रेशनलाइजेशन

- दो उद्देश्य– घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने और अधिक निर्यात को सहायता देना
- 80 पुरानी छूटें पहले ही खत्म हो चुकी हैं
- इस वर्ष 400 से अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करके 1 अक्टूबर, 2021 से विकृतियों से मुक्त संशोधित सीमा–शुल्क संरचना स्थापित की जाएगी।
- अब से सीमा–शुल्क में कोई नई रियायत इसके जारी होने की तिथि से दो वर्षों के बाद 31 मार्च तक वैध होगी।

इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल फोन उद्योग

- चार्जर के कुछ पार्ट्स और मोबाइलों के सब–पार्ट्स पर कुछ छूट
- मोबाइलों के कुछ पार्ट्स पर ड्यूटी नील दर से 2.5 प्रतिशत तक संशोधित की गई

लौहा और स्टील

- गैर–मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलैस स्टील के अर्ध, एक समान और लंबे उत्पादों पर सीमा–शुल्क एक समान रूप से 7.5 प्रतिशत कम करने की घोषणा की।
- 31 मार्च, 2022 तक स्टील स्क्रैप पर शुल्क में छूट दी गई
- एंटी–डंपिंग ड्यूटी (**ADD**) और काउंटर–वीलिंग ड्यूटी (**CVD**) कुछ स्टील उत्पादों से हटाया गया
- कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत

वस्त्र

- कैप्रोलैक्टम. नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर तथा धागे पर बीसीडी दरों को घटाकर 5 प्रतिशत किया गया.

रसायनों

- रसायनों पर सीमा–शुल्क दरों को अंशशोधित करने की भी घोषणा की ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिले और प्रतिलोमनों को हटाया जा सके।
- **Naptha** पर ड्यूटी 2.5 प्रतिशत की गई

सोना और चांदी

- सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाएगा

नवीकरणीय ऊर्जा

- सोलर सैल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विनिर्माण योजना को अधिसूचित किया जाएगा.
- घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, सोलर इनवर्टनरों पर शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और सोलर लालटेन पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा.

कैपिटल उपकरण

- टनल बोरिंग मशीन पर अब 7.5ः सीमा शुल्क लगेगाय और इसके पार्ट पर 2.5ः का शुल्क लगता है
- कुछ ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी सामान्य दर से बढ़कर 15प्रतिशत हो गई है

MSME उत्पाद

- स्टील स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया।
- 5प्रतिशत की पूर्व दर से 15 प्रतिशत की सीमा शुल्क को आकर्षित करने के लिए झींगा फीड
- परिधान, चमड़ा और हस्तशिल्प के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क–मुक्त वस्तुओं के निर्यात पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
- कुछ प्रकार के लेदर के आयात पर छूट
- घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार सिंथेटिक रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क बढ़ाया जाएगा

कृषि उत्पाद

- कपास पर सीमा शुल्क शून्य से 10ः और कच्चे रेशम और रेशम यार्न पर 10ः से बढ़कर 15ः किया गया.
- विकृत एथिल अल्कोहल पर अंत–उपयोग आधारित रियायत की वापसी
- छोटे सामानों पर कृषि बुनियादी ढांचे और विकास शुल्क (**AIDC**) का भी प्रस्ताव

न्यायसंगत अनुप्रयोगों और जटिलताओं को कम करना

- तुरंत कस्टम्स पहल, एक फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स उपाय
- ओर्गिन के नियमों के प्रशासन के लिए नई प्रक्रिया

बजट के बूस्टर से मंडियों को मिलेगी शक्ति

- 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा
- माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया
- एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ किया जाएगा

ए के त्रिपाठी

बजट में कृषि को लेकर की गई घोषणाएं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। चारों तरफ मचे किसान घमासान की पृष्ठभूमि में उम्मीद थी कि सरकार किसानों को लुभाने के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं, लेकिन बजट प्रावधानों को देखा जाए, तो कृषि के मोर्चे पर देश के कुछ लोगों को यह शून्य नजर आ रहा है।

क्या वास्तव में यह बजट कृषि के मोर्चे पर शून्य है? इसका उत्तर है– नहीं।

इस सवाल का जवाब बजट में ही ढूंढते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है, वह क्यों है। प्राानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही एग्री मार्केटिंग के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। जिसमें ई–नाम, ई–एनडब्ल्यूआर और कृषि सुधार कानून तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन उसके साथ ही किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को लेकर सरकार नेऐसी पहल की हैं, जो गेम चेंजर हैं। ऐसे में पिछले करीब 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन कुछ समूहों तक सीमित हों, लेकिन मोदी सरकार के लिए वे एक बड़े झटके के तौर पर सामने नहीं आए हैं। क्यों कि सरकार सब जानती है।

इसीमें कृषि को लेकर बजट में फैली चुप्पी का जवाब भी है। तीनों कृषि कानून, जिनके खिलाफ ये आंदोलन हो रहे हैं, वे दरअसल पिछले 7 सालों में कृषि को लेकर केन्द्र सरकार के किए गये तमाम प्रयासों का निचोड़ हैं। यदि सरकार को किसी भी हाल में ये कानून वापस लेने पड़ते हैं, तो सरकार के पिछले सारे नीतिगत प्रयासों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी साफ है कि, सरकार कोई भी नई घोषणा या नीतिगत पहल करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसान आंदोलन को लेकर बहुत कुछ नहीं करना है।

यूपीए की तुलना में सरकारी खरीद बढ़ाई

सीतारमन ने बजट भाषण में कृषि पर 12 पैराग्राफ समर्पित किए। इसमें 5 पैराग्राफ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर हुई सरकारी खरीद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए सीतारमन ने बताया कि, कैसे मोदी सरकार ने यूपीए की तुलना में सरकारी खरीद बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने पहले तो एमएसपी को लागत

का डेढ़ गुना किया और फिर किस तरह गेहूं, चावल, दलहन और कपास में यूपीए शासन के अंतिम साल यानी 2013–14 की तुलना में खरीदारी बढ़ाई। गेहूं और चावल में तो खरीदारी दोगुने से ज्यादा बढ़ी, लेकिन दलहन में तो यह मूल्य के लिहाज से 40 गुना और कॉटन में 288 गुना बढ़ी। आगे के आलेखों में इसका विवरण दिया जा रहा है।

पिछले आठ साल में कृषि जिंसों की एमएसपी खरीद और उससे लाभान्वित होने वाले किसान

साल	गेहूं		धान		कपास		जूट		दलहन	तिलहन
	एमएसपी कीमत (करोड़ में)	लाभार्थी किसान (लाख में)	एमएसपी कीमत (करोड़ में)	लाभार्थी किसान (लाख में)	एमएसपी कीमत (करोड़ में)	लाभार्थी किसान (लाख में)	एमएसपी कीमत (करोड़ में)	लाभार्थी किसान (लाख में)	एमएसपी कीमत (करोड़ में)	एमएसपी कीमत (करोड़ में)
2013–14	33874.20	उपलब्ध नहीं	63927.65	उपलब्ध नहीं	90	0.14	53.98	0.5	235.86	1626.39
2014–15	39232	उपलब्ध नहीं	66948	उपलब्ध नहीं	18506	29.5	6.56	0.06	1128.93	45.52
2015–16	40727.60	उपलब्ध नहीं	73981.90	73.08	1825	1.91	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही	15.90
2016–17	35015.53	20.47	85802.73	76.85	उपलब्ध नही	उपलब्ध नहीं	28.79	0.17	1039.39	946.71
2017–18	50089.00	31.87	90397.86	72.31	898	0.88	172.16	1.22	8566.13	5072.73
2018–19	6204.33	38.77	116839.47	96.94	2976	2.38	66.79	0.26	20145.60	7091.11
2019–20	62802.88	35.57	141928.08	124.59	28500	21.5	56.24	0.55	8284.45	8305.06
2020–21	75059.60	43.36	172752	154	25974	18.26	2.99	0.01	10530.20	3647.11

वितितमंत्री के दो पैराग्राफ
एपीएमसी (एग्री प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) मंडियों के प्रति सरकार की योजना का खुलासा करते हैं। पहली घोषणा, ई–नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) में 1000 मंडियों को जोड़ने की है और दूसरी, एपीएमसी मंडियों में बुनियादी ढांचे के विकास में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड (एआईडीएफ) का इस्तेमाल करने की अनुमति दिए जाने की है। ई–नाम योजना सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को शुरू की थी, जिसका लक्ष्य देश को एक मंडी प्लेटफॉर्म के रूप में बदलना है। इसमें अब तक 1000 मंडियां जुड़ चुकी हैं और इस बजट की घोषणा के बाद अब इस नेटवर्क में अगले साल तक 2000 मंडियां शामिल हो जाएंगी।

मंडियां अत्याधुनिक डिजिटल

ई–नाम में शामिल होने का मतलब यह है कि, देश की 7000 में से 2000 मंडियां अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित होंगी। इन्हें उपज की गुणवत्ता टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75 लाख रुपये मिलते हैं। इतना ही नहीं इनके विकास में एआईडीएफ की अनुमति का भी अपना बहुत साफ संदेश है। आंदोलनकारी किसानों नेयह आशंका जताई है कि एपीएमसी मंडी के बाहर फसलें बेचने की अनुमति देने से मंडियां गैर प्रतिस्पर्द्धी हो जाएंगी क्योंकि किसान वहां आएंगे नहीं और इसलिए उनकी आमदनी खत्म हो जाएगी, जिससे उनका बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाएगा। जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी सरकारों ने मंडियों को प्रतिस्पर्द्धी बनाए रखने के लिए मंडी फीस बहुत कम कर दिया है या खत्म ही कर दिया है। ऐसे में केंद्र ने एपीएमसी मंडियों के लिए वित्त की व्यवस्था कर साफ कर दिया है कि वह किसी भी हाल में मंडियों को कमजोर नहीं होने देना चाहता।

किसानों को 16 लाख करोड़ कर्ज

किसानों को कर्ज देने का टारगेट 16 लाख करोड़ रुपए किया गया। इस साल स्वामित्व स्कीम शुरु किया गया। अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा। 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार (e-NAM)और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एपीएमसी को फंड उपलब्ध कराया जाएगा।एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।

सरकार का यह बजट कृषि के लिहाज से पूरी तरह किसान के साए में बना है। सरकार ने एमएसपी और एपीएमसी के मुद्दे पर पूरे जोर से यह संदेश दिया है कि इन पर कोई खतरा नहीं है। और अब वह किसानों की प्रतिक्रिया का इंतजार करेगी। इस लिहाज से किसानों के इस आंदोलन को कृषि क्षेत्र में युगांतकारी सुधारों का एक संक्रमण काल माना जाना चाहिए। यदि आंदोलन जीतता है तो सुधारों का यह चक्र वापस पीछे लौटेगा और भारत में किसानों की नियति पुरानी बेड़ियों में ही जकड़ी रहेगी। लेकिन यदि सरकार अपने इरादों में कामयाब होती है तो यह चक्र एक नए युग का सूत्रपात करेगा। और फिर आने वाले दिनों में हम कृषि क्षेत्र के लिए कई नई घोषणाएं देख सकते हैं।

आम बजट 2021–22 में खास

- सरकार ने कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने संरचनात्मक सुधारों की गति को तेज किया
- भारत के पास कोविड–19 महामारी के दो टीके हैं, दो और टीके जल्दी ही आएंगे
- अब तक केवल तीन बार अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है
- सरकार ने गरीबों की मदद के लिए अपने संसाधनों का यथासंभव पूरा उपयोग किया हैरू वित्त मंत्री
- सरकार सतत और भरोसेमंद वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था के समर्थन को लेकर पूरी तरह से तैयाररू वित्त मंत्री
- बजट प्रस्ताव स्वास्थ्य और जन कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी सहित छह स्तंभों पर आधारित हैं रू सीतारमण
- 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव
- अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा
- सरकार 2021–22 में कोविड–19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये देगी और अधिक धन देने के लिए प्रतिबद्ध
- उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- पीएलआई योजना के अलावा वृहद निवेश कपड़ा–पार्क योजना की जाएगी शुरू
- वित्त मंत्री ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव
- सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिए लाएगी विधेयक
- ढांचागत क्षेत्र की पुरानी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के लिए लाई जाएगी योजना
- रेलवे मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए गए विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी
- गेल इंडिया लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा
- वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा
- सड़क बुनियादी ढांचा और बेहतर करने के लिए मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा
- वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिए 3,400 करोड़ रुपये आबंटित किए
- पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को दो लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी
- ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा
- रेलवे को 2021–22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं
- शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना
- पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किए गए, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावॉट की स्थापित क्षमता जोड़ी गई
- बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के

लिए तैयार की जाएगी रूपरेखा

- सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा
- हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव
- व्यापारिक–जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जाएगी एक सब्सिडी योजना
- मुफ्त रसोईं–गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा
- शहरी गैस वितरण नेटवर्क के जरिये सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी
- सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर का प्रस्ताव
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई
- बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव
- एनसीएलटी ढांचे को किया जाएगा मजबूत
- लघु कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा, इसमें मौजूदा पूंजी की 50 लाख रुपये की सीमा बढ़ा कर की जाएगी दो करोड़ रुपये
- बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश को 2021–22 में पूरा किया जाएगा
- गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए साझा परिवहन क्षमता के नियमन को लेकर परिवहन प्रणाली परिचालक (टीएसओ) की स्थापना की घोषणा
- वर्ष 2021–22 में लाया जाएगा एलआईसी का आईपीओ
- वित्त वर्ष 2021–22 लिए विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
- सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा, इस सत्र में पेश किया जाएगा कानून में संशोधन
- सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
- चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सार्वजनिक इकाइयों का विनिवेश किया जाएगा
- नीति आयोग से विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अगली सूची तैयार करने को कहा गया
- तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री ने कहा, कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की सरकारी खरीद से इस बार 43.36 लाख गेहूं कृषक लाभान्वित हुए
- किसानों को 2020–21 में एमएसपी पर गेहूं खरीद के एवज में 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया
- 2021–22 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया
- अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन बढ़ा कर 40,000 करोड़ रुपये किया गया, जो वित्त वर्ष 2020–21 में 30,000 करोड़ रुपए था
- ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम के तहत जल्दी खराब होने वाले 22 और जिंसों को शामिल किया जाएगा
- वित्त मंत्री ने मछली कारोबार के पांच बड़े केंद्रों के विकास की घोषणा की
- 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा
- कृषि मंडियों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा
- कृषि अवसंरचना कोष बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये तथा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कोष दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया गया
- सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ठेका कर्मचारियों को

भी शामिल किया जाएगा

- एक देश, एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों में क्रियान्वनाधीन
- लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
- अनुबंध से जुड़े विवादों के तेजी से समाधान के लिए सुलह व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव
- सिर्फ पेंशन आय वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने से छूट
- ठेका श्रमिकों, भवन और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी जमा करने के लिए पोर्टल का प्रस्ताव
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, 15,000 स्कूलों का मजबूत बनाया जाएगा
- युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षु कानून में संशोधन करेगी सरकार
- डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने वाली योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की योजना, पांच साल के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल का प्रस्ताव
- पांच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरा महासागर मिशन का प्रस्ताव
- नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक पेश करने का प्रस्ताव
- आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित, पहली बार डिजिटल तरीके से होगी जनगणना
- महामारी के कारण राजस्व प्रवाह पर प्रतिकूल असर, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को जरूरी समर्थन देने के लिए अधिक खर्च किए गए
- वाहनों के कुछ कल–पुर्जों, सौर उपकरणों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी
- कोविड–19 राहत के कारण चालू वित्त वर्ष में खर्च बढ़कर 34.50 लाख करोड़ रुपये हुआ, जबकि बजट अनुमान 30.42 लाख करोड़ रुपये
- आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 9.5 फीसदी पर, अगले वित्त वर्ष में 6.8 फीसदी रहने का अनुमान
- सरकार 2020–21 के शेष बचे दो महीनों में खर्च के लिए 80,000 करोड़ रुपये कर्ज लेगी
- बजट में पट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर कृषि बुनियादी ढांचा उपकर लगाया गया
- सरकार 2021–22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी, 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजी खर्च समेत कुल 34.83 लाख करोड़ रुपये व्यय का अनुमान
- स्टार्टअप के लिए कर अवकाश को एक साल के लिए बढ़ाया गया, स्टार्टअप में निवेश पर पूंजीगत लाभ पर छूट एक साल के लिए बढ़ी
- सरकार 2025–26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने को प्रतिबद्ध
- बजट में काबुली चने पर 30 फीसदी, मटर पर 10 फीसदी, बंगाल चने पर 50 फीसदी, मसूर पर 20 फीसदी, कपास पर पांच फीसदी कृषि अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव
- आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वर्ष 2020 में बढ़कर 6.48 करोड़ हुई, जबकि यह आंकड़ा वर्ष 2014 में 3.31 करोड़ था
- पिछले कुछ महीनों से जीएसटी संग्रह रिकार्ड स्तर पर, विसंगतियों का दूर करने के लिए हर संभव उपाय करेगी सरकार
- कर मामलों को दोबारा से शुरू करने के लिए समयसीमा छह साल से कम कर तीन साल की
- 50 लाख रुपये से अधिक की आय को छिपाने के गंभीर कर अपराधों को 10 साल बाद फिर खोला जा सकता है
- सरकार ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाने का प्रस्ताव किया है, राष्ट्रीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपये

स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र के लिहाज से 2,23,846 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय की तुलना में 137 प्रतिशत का इजाफा है। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए कोविड–19 के टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव भी रखा तथा देशभर में न्यूमोकोकल टीकों को उपलब्ध कराये जाने की घोषणा भी की जिससे हर साल 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। वित्त मंत्री ने 2021–22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, "मैंने 2021–22 के लिए कोविड–19 टीकों के वास्ते 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। मैं जरूरत पड़ने पर और धन देने की प्रतिबद्धता जताती हूं।" उन्होंने कहा कि भारत पहले ही कोविड–19 के दो टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और देश में जल्द ही दो और टीकों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा सकता है। न्यूमोकोकल टीका निमोनिया, सेप्टीसीमिया और मेनिन्जाइटिस जैसे घातक संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी होता है। वित्त मंत्री ने कहा, "भारत में निर्मित न्यूमोकोकल का टीका अभी केवल पांच राज्यों में ही सीमित है। इसे पूरे देश में उपलब्ध कराया जाएगा।" सीतारमण ने कहा कि इससे देश में हर साल 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी।

उज्ज्वला में एक करोड़ और लाभार्थी

मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना (उज्ज्वला) का विस्तार किया जाएगा तथा एक करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। 2021–22 के लिए आम बजट में कोविड–19 महामारी के दौरान ईंधन की अबाधित आपूर्ति जारी रखी गयी। घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को सीएनजी मुहैया कराने के सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार कर 100 और जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सामान्य वहन क्षमता के नियमन की खातिर परिवहन प्रणाली आपरेटर (टीएसओ) की भी घोषणा की।

दो करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली कंपनियां

लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा और इनके मौजूदा 50 लाख रुपये के पूंजी आधार को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021–22 के आम बजट में वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा। बैंकों की फंसे कर्ज की समस्याओं से निपटने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रबंधन कंपनी स्थापित की जाएगी, वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की रूपरेखा को मजबूत किया जाएगा।

विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021–22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों तथा एक बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री का इरादा है। बजट 2021–22 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसई) नीति पेश करते हुए कहा कि चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। यह नीति रणनीतिक और गैर–रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की स्पष्ट रूपरेखा पेश करेगी। अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लि. और अन्य कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। इसके अलावा एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए विधायी संशोधन भी 2021–22 में लाए जाएंगे। नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की अगली सूची पर काम करने को कहा गया है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्वामित्व वाली जमीनों के मौद्रिकरण (बिक्री–पट्टेदारी) के लिए एक विशेष इकाई (एसपीवी) बनाई जाएगी। अपने पिछले 2020–21 के बजट में निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार अभी तक चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री और शेयर पुनर्खरीद से 19,499 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

बजट

सुशिक्षित समाज

- 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा नीति के अनुसार 15,000 स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा
- राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी। 15,552 आदर्श विद्यालयों के लिए 4,684 करोड़ आवंटित

जल संरक्षण

- शहरी आबादी के लिए जल–जीवन मिशन लांच। पांच साल में घर–घर स्वच्छ जल पहुंचाने की तैयारी
- 4,378 शहरी निकायों में 2.86 करोड़ नल कनेक्शन के जरिये जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी

जनसंख्या नियोजन

- बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत भर्तियां होंगी। मेट्रो परियोजनाओं के तहत नए रोजगार बनेंगे
- कपड़ा उद्योग के 7400 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मेडिकल क्षेत्र में युवाओं की बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी

गरीबी उन्मूलन

- पूरक पोषण कार्यक्रम व पोषण अभियान का आपस में विलय करके मिशन पोषण 2.0 लांच
- 112 जिलों में पोषण के लिए रणनीति बनेगी। आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 को 20,105 करोड़ आवंटित

नारी सशक्तीकरण

- सभी कार्यस्थलों में हर शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं। रात्रि शिफ्ट में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी
- चाय बगान में काम करने वाली महिलाओं के लिए भारी भरकम आवंटन

पर्यावरण संरक्षण

- पांच साल में स्वच्छ हवा के लिए 2217 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 42 शहरी केंद्रों पर दिया जाएगा विशेष ध्यान
- पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। निजी गाड़ी 20 साल, कमर्शियल 15 साल बाद स्क्रैप में जाएगी

स्वस्थ समाज

- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे
- 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट चालू होंगी

10 जरूरी बातों पर ध्यान जरूरी!

ग्राहक के लिए बजट

वित्त मंत्री के इस बजट की काफी तारीफ हो रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि, निर्मला सीतारमण ने ग्राहकों के खर्च को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में कई बड़े सुधार किए हैं। एक ग्राहक के रूप में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस बजट से देश में मांग को कैसे बढ़ावा मिल सकता है।

इमिटेशन ज्वेलरी की कीमत

नए बजट प्रावधान के मुताबिक सिंथेटिक कीमती पत्थर के आयात पर अब कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसे 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी में रुचि रखते हैं तो जिस ज्वेलरी की कीमत अब तक ₹10000 होती थी अब उसकी कीमत ₹10250 हो जाएगी।

सोना–चांदी हुआ सस्ता

बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोना और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। अब तक अगर 10 ग्राम का सोने का सिक्का आपको ₹51000 का पड़ता था तो अब इसकी कीमत ₹850 तक घट जाएगी।

इंसुलेटेड केबल पर टैक्स

अगर आप आयातित इंसुलेटेड केबल से अपने घर को शॉक प्रूफ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी जेब पर अधिक भार बढ़ाना होगा। इस तरह की चीजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5: से बढ़ाकर 10: कर दी गई है। अगर अब तक इंपोर्टेड इंसुलेटेड केबल की कीमत ₹500 प्रति मीटर थी तो अब इसके लिए आपको ₹512 प्रति मीटर चुकाने होंगे।

सोलर इनवर्टर महंगा

अगर आप भी सोलर पैनल लगाकर धूप से बिजली बनाना चाहते हैं, तो अब आपको इसके लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। सोलर इनवर्टर के आयात पर ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है। सोलर लैंप पर ड्यूटी पांच से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी गई है। अगर लुमिनस के आयातित सोलर इनवर्टर की बात करें तो अब तक इसकी कीमत ₹3,50,000 पड़ती थी अब यह करीब ₹4,00,000 का पड़ेगा।

घर सजाना हुआ सस्ता

अगर आप भी अपने घर को सजाना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। मार्बल और ट्रैवर्टाइन ब्लॉक पर कस्टम ड्यूटी 44 से घटकर 40 फीसदी हो गई है। इसकी वजह यह है कि सोशल वेलफेयर सेस से इन प्रोडक्ट को छूट दी गई है। अगर आपके घर में इटालियन मार्बल लगाने का खर्च इस समय ₹10 लाख आता है तो कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद आपको इसमें करीब ₹30,000 बचाने में मदद मिलेगी।

सेब पर ड्यूटी घटी

अगर आप भी आयातित सेब खाने में रुचि लेते हैं तो नए वित्त वर्ष में सरकार ने आपके लिए खुशखबरी दी है। आयातित एपल पर अब प्रभावी कस्टम ड्यूटी 70 से घटाकर 50 फीसदी कर दी गई है। अगर बात न्यूजीलैंड से आयात किए जाने वाले सेब की करें तो इस समय वह ₹250 किलो बिक रहा है जो आपको नए वित्त वर्ष में ₹200 प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा।

ग्रॉसरी शॉपिंग में राहत

बजट में की गई घोषणा के हिसाब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काबुली चना, काला चना, मसूर, मटर आदि पर कस्टम ड्यूटी 70 प्रतिशत से घटाकर 40 से 60 फीसदी तक रखी है। अगर इनमें से कोई आयातित चीज आपको अब तक ₹500 किलो पड़ती थी तो अब वह आपके लिए ₹70 सस्ती हो जाएगी।

आयातित एलईडी बल्ब महंगा

अगर आप भी आयातित एलईडी पसंद करते हैं तब आपको इसके लिए अपनी जेब पर भार बढ़ाना पड़ेगा। एलईडी बल्ब के लिए कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी गई है। अब अगर आप 6 वाट का एलइडी लाइट खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत ₹7500 से बढ़कर ₹7800 हो जाएगी इसलिए भारतीय कंपनियों की एलईडी खरीद कर घर को रोशन करें।

आयातित इलेक्ट्रॉनिक खिलौने महंगे

अगर आप अपने बच्चे को आयातित इलेक्ट्रॉनिक खिलौने देना चाहते हैं तो इसकी कीमत दो से चार फीसदी बढ़ सकती है. सरकार ने इस पर कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है। अगर आप अपने बच्चे को आयातित कंपोनेंट की मदद से बने रिमोट कंट्रोल कार देना चाहते हैं जिसकी मौजूदा कीमत ₹5000 है तो अब आपको इसके लिए ₹5200 चुकाने पड़ेंगे।

आयातित वाइपर हुआ महंगा

अगर आपको वाहन में इंपोर्टेड एक्सेसरीज लगाना पसंद है तो अब आपको इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। विंडस्क्रीन वाइपर, डिफ्रोस्टर, डिमीस्टर और सेफ्टी ग्लास आदि पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। अगर आप बॉस का विंडशील्ड वाइपर लगाना चाहते हैं तो इसकी कीमत अभी ₹3000 थी जो आपको 1 अप्रैल के बाद 3150 रुपए पड़ेगी।

बजट 2021 : पीएसयू की हिस्सेदारी

विनिवेश से होगी सरकार को आमदनी

बजट में सरकार अपने खर्च पूरे करने के लिए विनिवेश पर बड़ा दाँव खेल रही है।

वित्त वर्ष 2020–21 में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर दो लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह करीब 20,000 करोड़ रुपये की जुटा सकी। पिछले साल बड़े विनिवेश की योजना तैयार की गई थी जिसमें एलआईसी के शेयर बेचे जाने की बात भी शामिल थी। एलआईसी की इस योजना को इस साल पूरा किया जा सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 1.05 लाख करोड़ और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा था।

राजकोष की हालत

विनिवेश के रूप में सरकार का बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का मतलब यह है कि उसके जरूरी खर्च उसकी आमदनी से पूरे नहीं हो रहे हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि सरकार अब उन कंपनियों में भी विनिवेश करना चाहती है जो अब तक उसके लिए पिगी बैंक की तरह काम कर रहे थे।

जीवन बीमा निगम बिक्री

वास्तव में भारत सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को अब तक अपने बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उस पर सरकार उन कंपनियों के शेयर खरीदने बेचने के लिए दबाव डाल सकती थी जिसमें दूसरे निवेशक निवेश करने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अब सरकार अगले वित्त वर्ष में एलआईसी को भी शेयर बाजार में लिस्ट कराने जा रही है। इससे बीमा क्षेत्र में बड़ा उछाल आने और भारी राजगार उत्पन्न होने की ओर कदम बढ़ेगा।

आईडीबीआई बैंक में विनिवेश

सरकार विनिवेश के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दो सरकारी बैंक और एक बीमा कंपनी समेत पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड समेत कई अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाना चाहती है। इससे न केवल ढांचागत योजनाओं में लाभ होगा बल्कि निजी क्षेत्र के आने से रोजगार भी मिलेगा।

संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर ध्यान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में जब व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी की घोषणा की या एनर्जी ट्रांजिशन और शहरों के प्रदूषण को कम करने के लिए फंड के आवंटन की घोषणा की तो इसका पूरा फोकस अपने संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना था।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल

यह वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुरूप ही था। संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वास्तव में सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजप्शन पर बात करता है। इस काम में भारत के कंपनियों की बड़ी भूमिका साबित हो सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ काम करने की वजह से भारत की कंपनियों का भविष्य सुरक्षित होगा। वास्तव में भविष्य में कारोबार करना और संसाधनों की बढ़ती प्रतियोगिता के इस दौर में कार्बन एमिशन को कम रखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

कार्बन यूटिलिटी पर काम

इस समय भारत की 24 कंपनियां सरकार के साथ हाथ मिलाकर कार्बन यूटिलिटी की तरह काम कर रही हैं. इनमें टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वेदांता, अंबुजा सीमेंट आदि शामिल है।

उद्योग में कार्बन उत्सर्जन

इस समय कंपनी जितनी अपने प्रोडक्ट से जितनी कमाई कर रही है उसमें 89 प्रतिशत लो कार्बन प्रोडक्ट्स है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर भी इको लेवल दिखाने पर काम कर रही है। इससे वास्तव में कार्बन के उत्सर्जन में कमी, सामान के दोबारा उपयोग और रीसायकल करने की क्षमता आदि का पता चलता है।

इंडस्ट्री रखे ध्यान

कंपनियों को उन संसाधनों का यूज कम करना चाहिए जो क्रिटिकल है। अब भारत की अर्थव्यवस्था कोरोनावायरस शॉक से उबर रही है तो इस बात पर रिसर्च बढ़ाया जाना चाहिए कि संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है जिससे कार्बन का उत्सर्जन घटाने में मदद मिले।

चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन

बजट ने नए करों के बारे में विशेषज्ञों की आशंकाओं को झुठलाया : प्रधानमंत्री

पहले बजट केवल वोट–बैंक की गणनाओं का बहीखाता ही होता था, अब राष्ट्र ने अपना दृदृष्टिकोण बदल दिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में 'चौरी–चौरा' शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे हो गए है। यह घटना स्वधतंत्रता के लिए देश की लड़ाई की एक ऐतिहासिक घटना है। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने बहादुर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि चौरी–चौरा में दिए गए बलिदान ने देश के स्वपतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा में सौ साल पहले हुई यह घटना केवल आगजनी की घटना नहीं थी बल्कि चौरी चौरा का संदेश बहुत व्यापक था। यह आगजनी की घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण थे, ये सब समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे देश के इतिहास में चौरी चौरा के ऐतिहासिक संघर्ष को उचित महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौरी–चौरा के साथ–साथ हर गांव पूरे वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में इस घटना के वीर बलिदानियों को याद करेगा। उन्होंने कहा कि यह समारोह ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब देश अपने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इससे यह आयोजन और भी प्रासंगिक हो जाएगा। उन्होंने चौरी–चौरा के शहीदों के बारे में चर्चा कम होने के बारे में खेद व्य क्त किया। उन्होंने कहा कि इस घटना के शहीदों का भले ही इतिहास के पन्नों में प्रमुखता से उल्लेख न हुआ हों, लेकिन उनका खून निश्चित रूप से स्वशतंत्रता की लड़ाई में देश की मिट्टी में जरूर मिला है।

प्रधानमंत्री ने लोगों से बाबा राघवदास और महामना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों को स्मरण करने का अनुरोध किया, जिनके कारण इस विशेष दिन लगभग 150 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ने से बचा लिया गया था। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि इस अभियान में छात्र भी शामिल थे, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के कई अनकहे पहलुओं के बारे में उनकी जागरूकता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के अज्ञात बलिदानियों के बारे में एक किताब लिखने के लिए युवा लेखकों को आमंत्रित किया है।

आगरा जिले के किरावली मण्डल में मन की बात

अलीगढ़ में बूथ अध्यक्षों एवं सेक्टर संयोजकों की बैठक

जिला आगरा के बिचपुरी मण्डल की बैठक

सहारनपुर जिला कार्यालय पर वार्ड अध्यक्षों व वार्ड सचिवों तथा स्थानीय पार्षदों के साथ बैठक

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2018-20
फरवरी प्रथम 2021 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 11–13 (प्रथम पाक्षिक)

चौरी–चौरा शहीद नमन

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी